

(b) The proposal made by the Supreme Court in the order dated April 2, 1980 is engaging the attention of this Ministry.

ऊपरि पुलों का निर्माण

6257. श्री सत्यनारायण जाटिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरों में से होकर गुजरने वाली रेल लाइनों द्वारा प्रभावित होने वाले यातायात में सुधार करने के लिये 'ऊपरि पुलों' का निर्माण करने की नीति है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अजमेर खंडवा मीटर लाइन के उन शहरों के नाम क्या हैं जहां ऊपरि पुल बनाये गये हैं/बनाये जा रहे हैं और बनाये जायेंगे तथा इनमें से प्रत्येक शहर में ऐसे कितने पुल होंगे;

(ग) बम्बई-दिल्ली बरास्ता रतलाम बड़ी लाइन पर नागदा मंडी और नागदा स्थित बिडलाग्राम औद्योगिक नगर के बीच यातायात के लिये 'ऊपरि पुल' के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मीस्ल-काजून): (क) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अनुसार किसी रेलवे लाइन के निर्माण के समय या उसके बाद 10 वर्ष के भीतर ऊपरि/निचले सड़क पुल और समपार जैसे अपेक्षित समायोजन कार्य रेलों द्वारा अपने खर्च पर किये जाते हैं। उसके बाद यदि कोई नया ऊपरि/निचला सड़क पुल बनाना पड़ता है (किसी वर्तमान समपार के बदले में नहीं) तो उसकी पूरी लागत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन की जानी अपेक्षित है।

व्यस्त समपारों पर दुर्घटनाओं से बचने और सड़क/रेल यातायात को रोकने न देने के लिए रेलों की नीति यह है कि वर्तमान समपारों के बदले ऊपरि/निचले सड़क पुलों का एक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण की हिस्सेदारी के आधार पर निर्माण किया जाए। इस प्रकार की परियोजनाओं का रेलों और राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त

रूप से कार्यान्वयन किया जाता है और अपने हिस्से की लागत वहन करने के आश्वासन के साथ इस तरह के कार्यों के प्रस्ताव भी राज्य सरकार/सड़क प्राधिकारियों द्वारा प्रायोजित किये जाने अपेक्षित हैं।

(ख) इन्दौर में दो पुलों का निर्माण किया गया था। कोई नया पुल नहीं बनाया जा रहा है और इस लाइन के किसी स्थान पर ऊपरि सड़क पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों को ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) 35.00 लाख रुपये।

Employment to persons who have become overage

6258. SHRI GHULAM RASOOL KOCHACK: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that registration in the Employment Exchanges has been on increase for the last two years;

(b) if so, whether in spite of number of projects undertaken by the State Governments, the vast majority of the unemployed youth is still out of job;

(c) whether this has resulted unrest among the large number of youths;

(d) whether the Central Government have taken any initiative to help those who have become overage and are ineligible to get Government employment; and

(e) if so, whether Government propose to remove this class of age and when the final decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJIAH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The number of job-seekers (all of whom are not necessarily unemployed) on the Live Register of Employment Exchanges as on 31st May,